भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक,
पटना (बिहार) 12–13 जून 2010

संप्रग (II) का एक वर्ष – निराषा और असफलता का वर्ष

संप्रग II के असंतोषजनक रिकार्ड की तरह ही संप्रग II के कार्यकाल का प्रथम वर्ष उदासीनता और गैर उपलब्धियों भरा रहा। अराजकता, भ्रम की स्थिति, सांठगांठ, भ्रष्टाचार, विसंगति और अव्यवस्था ही संप्रग की इस वर्ष की अलग तरह की विशेषताऐं रही। घोषणाएं अनेक हुई किन्तु कार्य नाम मात्र का रहा। इस सरकार की एक मात्र सफलता बस यही रही कि यह अपने सहयोगियों से भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कुटिल समझौते कर तथा विपक्ष के कुछ आलोचनीय पक्षों को अनैतिक ढ़ग से नियंत्रित कर कमजोर बहुमत के सहारे लोकसभा में तथा राज्यसभा में अल्पमत में रहते हुए भी सरकार बचाने में कामयाब रही।

मंहगाई

मई 2009, में सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार के लिए 100 दिनों का एजेन्डा तय किया। महंगाई को रोकना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। 365 दिन व्यतीत होने के बाबजूद मुद्रस्फीति के नीचे आने के कोई संकेत दिखाई नहीं देते। आम आदमी महंगाई की मार से निरंतर पीड़ित है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक दोहरे अंकों को छूने को है जबकि खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति 17–19 प्रतिशत पर है। महंगाई को बढ़ते हुए तीन वर्ष हो रहे हैं और यह स्थिति तब है जब सरकार की कमान डा० मनमोहन सिंह जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने थाम रखी है। खाद्‌य पदार्थो की महंगाई के लिए संप्रग सरकार द्वारा खाद्‌य कुप्रबंध सीधे तौर पर जिम्मेवार है।

किसानों और आम आदमी की कीमत पर सरकार ने बिचौलियों के हितों का सरंक्षण किया है। वस्तु विनिमय और खाद्य अर्थव्यवस्था अनाजों और अर्थव्यवस्था उत्पादों से सम्बंधित आयात और निर्यात नीतियों में भारी अनियमितता इस बात की हैं कि सरकार ने दलालों और बिचौलियों का संरक्षण किया। सरकारी अनाज गोदामों में जहाँ एक ओर अनाज सड़ रहा है वहीं दूसरी ओर किफायती और वाजिब दाम पर अनाज को बाजार में उपलब्ध न करवा पाने ने इस समस्या की विकरालता को बनाये रखा है।

यह अत्यन्त संतोष का विषय है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में राजग शासन के दौरान मंहगाई नियंत्रण में रही और बाजार में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। उस शासन के दौरान किसान और उपभोक्ता दोनों ही प्रसन्न थे। कई प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं के बावजूद की गई। खाद्य अर्थतंत्र के ठोस प्रबंधन को उपलब्ध कराया गया। कांग्रेसनीत केन्द्रीय सरकार अपनी कमजोर इच्छा शक्ति के कारण मंहगाई को नियंत्रित नहीं कर सकी। यह सरकार राष्ट्र को यह समझाने में असमर्थ रही कि राजग सरकार द्वारा छोड़ी गई अधिकता वाली खाद्य अर्थव्यवस्था, कैसे कमी और मंहगाई की अर्थव्यवस्था बन गई। अर्जित खाद्य अर्थतंत्र की समृद्धि, कमी और मंहगाई की अर्थव्यवस्था बन गयी।

कृषि और ढांचागत संरचना की असंतोषजनक दशा

ढांचागत संरचना और कृषि की दशा बहुत असंतोशजनक है। राजग के कार्यकाल में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम एक महान सफलता थी। वस्तुतः, राजग के कार्यकाल के दौरान किए गए सुशासन के कारण में 71 प्रतिशत सफलता की दर के साथ निर्धारित लक्ष्य जोकि बढ़कर 2004–05 में 81 प्रतिशत हो गया था। अनावश्यक विलंब, तदर्थवाद, पड़ताल की कमी और निर्णय प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, यहां तक की योजना आयोग और महालेखा नियंत्रक परीक्षक की विपरीत टिप्पणी के बावजूद संप्रग 1 अपने मार्ग से भटक गया था। अब यह दावा किया जाता है कि राजग के शासन काल में प्रतिदिन 11 किमी० सड़क निर्माण के लक्ष्य की तुलना में संप्रग द्वारा प्रतिदिन संशोधित कर 20 किमी० सड़क निर्माण किया जा रहा है। यह दावा केवल कागजी है। योजना आयोग ने लक्ष्य को 20 किमी० से 6 किमी० प्रतिदिन 'संशोधित' कर दिया है। 2009 – 10 के योजना आयोग की सड़क विकास रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय 29934.67 (30,000 करोड़) करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 11608 करोड़ रूपया ही खर्च कर सका, यानी कि 40 प्रतिशत के आस पास।

सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र जो विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अब गड्डमड्ड हो गया हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय स्वयं ऊर्जा क्षेत्र के प्रदर्शन पर अत्यन्न असंतुष्ट है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 1998–2003 के समय (राजग के कार्यकाल के दौरान) ऊर्जा मंत्रालय ने 2003 के इलेक्ट्रिसिटी विधेयक को समर्थन देते हुये सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके इस क्षेत्र को ऊंचाईयों तक पहुंचाया था। संप्रग के पांच वर्ष के शासन के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय के विवरण के अनुसार जो सूचना के अधिकार तहत उपलब्ध है, ' अवसर खोने के आधे दशक' जैसा हैं, जहां सुधार प्रक्रिया के प्रोत्साहन को छोड़ दिया गया है। वही हाल संप्रग 2 में भी जारी है जहां ऊर्जा क्षेत्र अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वस्तुतः बिजली उत्पादन की लगातार गिरावट ने हमारे सकल घरेलू उत्पाद को पीछे धकेल दिया हैं।

हवाई यातायात आधारभूत संरचना का बहुत महत्वपूर्ण अंग है अब नित नए सबूत संप्रग 2 के अधीन एयर इंडिया की वास्तविक मृत्यु के साक्ष्य है। संप्रग 1 के कार्यकाल के दौरान विकसित बीमारी संप्रग II की प्रथम वर्ष के कार्यकाल में कैंसर से ग्रस्त हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा देश की नदियों को आपस में जोड़ने की विस्तृत योजना की गई थीं इस परियोजना द्वारा हम देश में बाढ़ एवं सूखे की समस्या पर सामान्य रूप से नियंत्रण पा सकते हैं। देश के ऊर्जा संकट का निवारण भी इस माध्यम से 6000 मेगावॉट की पनबिजली का उत्पादन करके प्राप्त कर सकते है। संप्रग सरकार द्वारा इस परियोजना को समाप्त किया गया है। 2007 में इंडिया एयर लाईन्स और एयर इंडिया का विलय किया गया था और यह सलाहकार की रिपोर्ट पर आधारित था। हमें बताया गया था कि इस नए विलय से प्रतिवर्ष 500 करोड़ की बचत होगी। किसी भी टर्नओवर को किनारे रखते हुए विलय के बाद वर्त्तमान में घाटा बढ़कर 7200 करोड़ रू० का हो गया और अगले वर्ष 10,000 करोड़ रू० के लगभग हो जायेगा। हम बार– बार दुर्घटनाओं, बेवजह विलंब और अंतिम समय में दो हवाई जहाज के टकराने से बचने की रिपोर्ट सुनते रहते है। क्या संप्रग II को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में कुप्रबंधन की जबावदेही नहीं लेनी चाहिए ?

जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत कृषिक्षेत्र में है और उस पर निर्भर है। फिर भी यह सकल घेरलू उत्पाद में केवल 17 प्रतिशत योगदान देता है। लगातार बढ़ती हुई मंहगाई के कारण मुद्रास्फीति का प्रभाव इस क्षेत्र पर ज्यादा पड़ा है। 2009 – 10 में कृषि आमदनी बगैर सुधार के अत्यधिक असंतोषजनक रही। 31 मई 2010 को प्रस्तुत वार्षिक जी डी पी में कृषि आय में 0.7 प्रतिशत की नाममात्र की वृद्धि हुई है और यह हालात बदतर ही हैं। आज तक संप्रग II ने कृषि क्षेत्र की गंभीर

समस्याओं से निपटने के लिए कोई व्यापक और सम्पूर्ण योजना को प्रस्तुत नहीं किया है जोकि विकास के लिए बेहद गंभीर विषय है। किसानों की आत्महत्याऐं लगातार जारी है। कई घोषणाएं और राहत गरीब किसानों की चिंताओं का समाधान नहीं करती है।

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सही संख्या के बारे में भ्रम और अनिश्चिता की स्थिति बनी हुई हैं, जोकि समूचे सामाजिक विकास कार्यक्रम एवं खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। योजना आयोग के अनुसार 27.3 प्रतिशत ग्रामीण निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार द्वारा नियुक्त एन० सी० सक्सेना विशेषज्ञ समूह कैलोरी ग्रहण करने पर आधारित, के अनुसार 50 प्रतिशत ग्रामीण निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अर्जुन सेनगुप्ता आयेाग (गैर संगठित क्षेत्र उद्यमिता पर राष्ट्रीय आयोग) ने पाया है कि 77 प्रतिशत जनसंख्या 20 रू० प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करती हैं इसलिए यही मानदंड गरीबी रेखा का आधार होना चाहिए। सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहा था कि देश की जनसंख्या का 37.2 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे है यह ध्यान देने की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विकास सूचकांक ने भारत को भूटान से भी नीचे 132वें स्थान पर रखा हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 88 विकासशील देशों में 65वें स्थान पर है। स्वाभाविक है कि बी पी एल परिवारों की सटीक संख्या के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। क्योंकि इसकी सटीक संख्या नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा का कोई भी निवाला अर्थहीन होगा संप्रग 2 को अभी भी यह औपचारिक रूप से घोषित करना है कि बी पी एल परिवारों की वास्तविक संख्या कितनी है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि रोजगार सृजन संप्रग के लिए न्यूनतम प्राथमिकता क्षेत्र में आ गया है। पहले यह प्रतिवर्ष 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की ढ़ींग मारता था। अब यह बेहद निराश रिकार्ड के बाद समाप्त हो चुका है। बड़ी संख्या में बेरोजगारी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लाखों युवाओं के लिए लगातार अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है और संप्रग II लगातार उदासीन बना हुआ हैं।

विदेश नीति

ऐसा लगता है कि संप्रग II की सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में भारतीय विदेश नीति के प्रबंधन में उसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के तत्वों पर आघात पहुँचाया है। पूर्व में रणनीतिक मुद्दों पर भारत अंतरराष्ट्रीय दवाब के समक्ष दृढ़ता से खड़ा था, अब उसकी कमी नजर आती है। शर्म–अल–शेख की संयुक्त घोषणा देश के लिए सिर्फ शर्मनाक ही नहीं थी बल्कि जनवरी 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच संयुक्त उद्घोषणा के विपरीत थी। जिसमें पाकिस्तान ने पहली बार यह स्वीकार किया था कि वह अपनी भूमि से आतंकी गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा। बलूचिस्तान को संदर्भ में लाना शर्म–अल–शेख वार्त्ता की भंयकर भूल थी। अब संप्रग ने भारत के राजनीतिक हितों के खिलाफ जाते हुए यह निर्णय कर लिया है कि पाकिस्तान के साथ वार्त्ता में सीमा पार से हो रही आतंकी गतिविधियों को दरकिनार करते हुए वार्त्ता की जायेगी। इस प्रकार से भारत की पारम्परिक विदेश नीति को क्षति पहुँचायी गई है। कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन के विषय पर मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में भारत की भूमिका पर अमेरिका का दवाब इस बात का सबूत है। इसी प्रकार सिविल परमाणु दायित्व विधेयक जिस प्रकार हड़बड़ी में तैयार किया गया और आगे बढ़ाया गया, इसमें भी अमेरिका का दवाब स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस विधेयक के माध्यम से भारत में परमाणु संयंत्रों को सिर्फ पब्लिक सेक्टर के द्वारा संचालित करने की अुनमति देना, इस बिल की निरर्थकता को दर्शाता है। अगर यह परमाणु बिल परमाणु ऊर्जा संयत्रों को अमरीकी आपूर्ति कत्ताओं के हितों के हेतु बनाया गया है। तो इसमें दुर्घटना के मद्देनजर अपराधिक जिम्मेवारी तथा एक उचित मुआवजे के व्यवस्था करने के प्रावधानों की भी आवश्यकता थी। किसी भी भारतीय नागरिक का जीवन किसी भी अमेरिकन या अन्य किसी के जीवन से सस्ता नहीं है। भोपाल त्रासदी काण्ड से पीड़ित लोगों के साथ जो घोर अन्याय किया गया है, उसका संदर्भ इस मामले में बहुत

अच्छी तरह से समझा जा सकता है। भाजपा यह मांग करती है कि वे सभी आवश्यक कदम उठाये जाएं जिससे भोपाल त्रासदी से पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके।

आतंकवाद पर नरमी

संप्रग I की तरह संप्रग II आतंकवाद पर नरम है। यह आतंकवादियों और उनके आकाओं को, जो देश के भीतर और बाहर अपना काम कर रहे हैं, निरंतर यह संदेश दे रहा है कि वोट बैंक की खातिर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही को अदला बदला जा सकता है। इसकी सबसे शर्मनाक पुष्टि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की सार्वजनिक अभिव्यक्ति में देखी जा सकती है जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया कि अफजल गुरू जिसने संसद पर आतंकी हमला किया, जिसके चलते सर्वोच्च न्यायालय ने उसे मौत की सजा दी, उसके माफीनामे के आवेदन पर कोई कारवाई न की जाय, इसके लिए तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने दवाब बनाया। इस कारण यह फाइल तीन वर्षों से अधिक समय तक धूल चाटती रही। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान दिग्विजय सिंह उस आंतकवादियों के परिवार से मिलने आजमगढ़ गये जो अपने अन्य साथियों के साथ बाटला हाऊस दिल्ली में मारा गया। बाटला हाऊस मुठभेड़ में एक बहादुर पुलिस अधिकारी श्री मोहनलाल शर्मा शहीद हो गये। बावजूद इसके कांग्रेस के महासचिव और केबिनेट के अन्य कई मंत्री वोट बैंक की राजनीति के करण इस पूरे मामले केा संदेहास्पद बनाने के लिये अनेक प्रश्न खड़े करते रहे हैं। सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दवाब बनाने के मामले में भारत ने अपनी स्थिति कमजोर कर ली है। 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के बावजूद भारत, पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिये लालायित दिखाई पड़ता है जबकि पाकिस्तान लगातार मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमांइडों के खिलाफ कारवाई टालता आ रहा है। 26/11 के अभियोजन मामले में सिर्फ एक को सजा हुई है बाकि किसी अन्य पाकिस्तानी जिन्होंने योजना बनाई और फिर इसको कार्यान्वित किया, के खिलाफ कोई भी उल्लेखनीय कार्रवाई नहीं हुई। 26/11 मामले में भारतीय खुफिया एजेन्सियों और जाँच एजेन्सियों द्वारा डेविड हेडली की भूमिका को उद्घाटित नहीं कर पाना जाँच एजेन्सियों और खुफिया एजेन्सियों की घोर असफलता को दिखलाता है और यह साबित करता है कि हम कितने संवेदनशील है ?

माओवादियों द्वारा निरंतर नरसंहार किया जा रहा हैं। आतंकवादी समूहों और माओवादियों के बीच संबंधों की जानकारी यह उजागर करती है कि हम कितनी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे है।

भ्रष्टाचार

संप्रग II के कार्यकाल के प्रथम वर्ष ने एक बार फिर दिखाया गया है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में एक कठोर कार्यवाही करना तो दूर, कोई भी कार्यवाही करने के कितने लाचार है। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के निष्पादन में धीमेपन ने भी भ्रष्टाचार को बढ़ाने में योगदान दिया है, योजनाओं के तहत कार्यो को सौपने में नाजायज प्रभाव परिलक्षित होता है। 2 जी० स्पेक्ट्रम मामले में भारतीय राजस्व को 60 हजार करोड़ का चूना लगा। अब जबकि सी बी आई ने जाँच कर आरोपों को सच पाया तो प्रधानमंत्री अपनी अधिकारों का प्रयोग करने में अक्षम हैं और सम्बन्धित मंत्री को हटा नहीं पा रहे हैं।

आईपीएल क्रिकेट फ्रेंचाइजी प्राप्त करना या चीनी कम्पनियों में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए मंत्रियों की लाबिंग करने के आचरण को संप्रग सरकार ने गंभीर मुद्दों के अस्तित्व में होने के बावजूद स्वीकार कर लिया हैं। इस कैबिनेट के मंत्री एक–दूसरे पर लगातार सार्वजनिक हमले कर रहे हैं। राष्ट्रीय

ग्रामीण गारन्टी रोजगार योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार के प्रमाण मिले है। भाजपा इस विषय की गहराई से अध्ययन करेगी एवं भ्रष्टाचार को सामने लाएगी।

संस्थाओं का दुरूपयोग

संप्रग सरकार के प्रथम और द्वित्तीय कार्यकाल की एक स्थायी विशिष्टता यह है कि उसने शर्मनाक ढंग से सी बी आई का दूरूपयोग किया है। आय से अधिक आमदनी के एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के मामले में विचार करने के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ याचिका सी बी आई द्वारा उच्च न्यायालय में अपील के लिये एक गंभीर अनुशंसा के बावजूद दायर नहीं की। जब बिहार सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में अपील को स्वीकार कर लिया तो सी बी आई ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद कि सिर्फ सी बी आई ही निर्णय के खिलाफ चुनौती दे सकती है सरकार ने सी बी आई को अपील दायर करने की अनुमति नहीं दी। मंहगाई के मामले में लालू प्रसाद द्वारा सरकार की खिचाई के बावजूद कटौती प्रस्ताव के दौरान मतदान के समय संप्रग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढ़ग से मदद की गयी। संप्रग एक के शासन के दौरान जब लेफ्ट ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो सरकार बचाने के लिए श्री मुलायम सिंह यादव का समर्थन लेने के लिये सी बी आई का एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। यही तरीका संप्रग द्वारा दो शासन के दौरान कटोती प्रस्ताव के समय मायावती और बी एस पी का समर्थन लेने के लिये अपनाया गया। विपक्ष से जुझने के लिये कानूनी और गैर कानूनी फोन टेपिंग का सहारा लिया गया। लाबिंग करने वाले सरकार के भीतर और बाहर से अपने कामों को अंजाम देते रहें।

भाजपा की भूमिका

पिछले एक वर्ष में, भाजपा ने ही जोश खरोश के साथ यह साबित किया कि सिर्फ उसी ने संप्रग II की जनता विरोधी नीतियों और शासन का पर्दाफाश किया है और सिर्फ वही अपने सहयोगियों के साथ गैर संप्रग का विकल्प है। पिछला एक वर्ष भाजपा के लिए खासतौर से उल्लेखनीय हैं। हमें नये अध्यक्ष और संसद के दोनों सदनों में नया नेतृत्व मिला है। पार्टी संगठन की पुर्नसंरचना राज्य स्तर तक की गयी है। इसकी एक शक्तिशाली उपस्थिति है और इसकी गतिविधियाँ संपूर्ण देश में व्याप्त है। पार्टी कार्यकर्त्ता निरंतर संप्रग के असफलताओं का देश के सभी भागों में विरोध कर रहे है। कई अवसरों पर संसद के दोनों सदनों में हमने सफलापूर्वक सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर किया हैं। जिस भी राज्य में भाजपा की सरकार है वहां हमने आम आदमी के हितों से सम्बन्धित शासन का नमूना पेश किया है। भाजपा एक राष्ट्रवादी विपक्ष की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेवारी निभाने के लिये प्रतिबद्ध है।